मोदी जी अपनी गरीबी की दुकानदारी अब बंद कीजिए

आप उत्तर प्रदेश की एक जनसभा में अपनी गरीबी बेच रहे थे। ऐसा है अगर प्रधानमंत्री हो जाना ही सबकुछ हो जाना है तो लालबहादुर शास्त्री भले ही पिछड़े वर्ग से नहीं थे मगर बेहद गरीबी में पलेबढ़े थे और प्रधानमंत्री होकर भी उनके पास दो जोड़ी कपड़े होते थे और कभी कुर्ते तथा कभी उनकी धोती में छेद होते थे। अगर गरीब होना ही सबकुछ होना होता है तो हमारे कम से कम दो राष्ट्रपति बेहद गरीबी से निकले थे-के आर नारायणन और एपीजे अब्दुल कलाम। नारायणन तो दलित थे और अब्दुल कलाम भी बचपन में अखबार बेचकर गरीबी से लड़े थे। और ये तीनों गरिमामय पदों पर बैठकर बेहद गरिमामय व्यवहार करते थे और अपनी गरीबी की बारहों महीने सेल नहीं लगाते थे। ये छिछले लोग नहीं थे।

एक और बात। लिओ ताल्सताय और रवीन्द्रनाथ टैगोर गरीब नहीं थे लेकिन आप उनके पाँव की धूल का एक कण भी नहीं हैं। और महात्मा गांधी ने तो देश के करोड़ों लोगों की जिन्दगी देखकर गरीबी का वरण किया था। नेहरू जी के नाम से आपकी प्रजाति को मिर्ची लगेगी, इसलिए फिलहाल उन्हें छोड़ता हूँ। और अपनी गरीबी का रोना रोनेवाला शख्स अमीरों को भी लजा देनेवाली अमीरी में जीता है और उनका ही असली हितचिंतक है,यह हम कैसे भूलें ?

एक अंतिम बात। महोदय हिंदुस्तान में तब आप ही नहीं करोड़ों लोग इन्हीं परिस्थितियों से जूझ रहे थे और आज भी जूझ रहे हैं। कहीं मत जाइए प्रधानमंत्री का तामझाम छोड़कर साधारण कार में सुबह सात बजे दिल्ली शहर के सैकड़ों लेबर चौक घूम जाइए। अपनी मेहनत बेचने के लिए लोग खड़े-बैठे रहते हैं और ग्यारह- बारह बजे तक भी कइयों को काम नहीं मिलता। उनके पेट में उस दिन कुछ जाता है या नहीं,कौन जानता है? आज भी कैसी भयानक गरीबी है,क्या बताएँ। और मोदीजी आप किसी यूरोपीय देश के नेता नहीं हैं, जिनकी दो -तीन पीढियों ने हम जैसी गरीबी नहीं देखी है। आप उन्हीं गरीबों को अपनी झूठी -सच्ची दास्तान सुना रहे हैं,जो आज भी आपसे कई गुना गरीबी और अपमान झेलकर जी रहे हैं। इनके सामने अपनी गरीबी का रोना रोते हुए एक बार भी आपको शर्म नहीं आती ? झिझक तक नहीं होती ? कैसे गरीब थे आप और कैसे प्रधानमंत्री हैं आप! -विष्णु नागर

संक्षेप में कुछ बातें और। गरीबी से निकलकर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो जाना ही सबकुछ नहीं होता। लोग आपकी गरीबी को नहीं,आपके कारनामों को याद रखेंगे और आपके भक्तों की नाराजगी मोल लेते हुए कहूँगा कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है कि लोग आपको पद से हटने के पाँच साल बाद भी सम्मान से याद रखें।

सुधी पाठकों से अपील

गोदी मीडिया सत्ता की गोद में बैठ कर खबरों को दबाने व भ्रमित करने का काम कर रहा हो तो 'मज़दूर मोर्चा' जैसे वैकल्पिक मीडिया को मजबूत करना आज की जरूरत है। पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान सुधी पाठकों ने देखा होगा कि आपका यह छोटा सा मोर्चा किसी राजनेता का भोंपू नहीं बना, किसी का यशोगान नहीं किया और न ही किसी के विज्ञापन छापे।

'मज़दूर मोर्चा' केवल पाठकों के सहयोग से चलने वाला साप्ताहिक है। पाठक ही इसके संवाददाता हैं और पाठक ही संरक्षक। आपका यह साप्ताहिक और अधिक एवं सटीक खबरें आप तक पहुंचा सके इसके लिये आपके आर्थिक सहयोग की सख्त जरूरत है। 'मज़दूर मोर्चा' एक व्यक्ति से 100 रुपये चंदा लेने की अपेक्षा सौ लोगों से एक-एक रुपये का सहयोग लेना अधिक पसंद करता है। अतः अपनी आवाज़ को बुलंद करने व दबी-छिपी तमाम खबरों को जानने के लिये 'मज़दूर मोर्चा' को यथा-शक्ति आर्थिक सहयोग करें।

धन्यवाद

- सम्पादक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में

खाता संख्या : 451102010004150

IFSC CODE : UBIN0545112

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
5. राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
6. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
7. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207

गतांक की चीर-फ़ाड़

चुनाव में मोदी व शाह को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 12-18 मई 2019 के अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, साहित्यिक व आर्थिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुए हैं। भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य दो चुनाव आयुक्तों से भारत के प्रत्येक नागरिक को आशा है कि वे अपने संवैधानिक दायित्व को निष्पक्षता व निष्ठापूर्वक निभायेंगे तथा किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। व किसी भी नेता के दबाव में नहीं आयेंगे और किसी भी राजनीतिक दल की सहायता नहीं करेंगे। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन शेषण ने अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा व निष्पक्षता से निभाया जिससे चुनाव आयोग के प्रति जनता का भरोसा बढ़ गया। परंतु 2014 के बाद से चुनाव आयेग के प्रति जनता का भरोसा कम होता गया। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने तो अपने संवैधानिक दायित्वों को निष्पक्षता से निभाने की बजाए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के सामने घुटने टेक दिए और प्रधानमंत्री मोदी को कई प्रकार की रियायतें दी, जिनका 'क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी आयोग बन गया है?' में खुलासा किया गया है।

पिछले लोकसभा चुनाव के बाद जब पांच राज्यों की विधानसभा चुनाव हुए तो गुजरात विधानसभाओं के चुनाव अन्य राज्यों के चुनाव के बाद करवाये गये जिससे मोदी जी व शाह को गुजरात में चुनाव प्रचार के लिये पर्याप्त समय मिल जाए। वर्तमान लोकसभा चुनाव के लिये चुनाव आयोग की प्रेस-कॉफ्रेंस टाली गई जिससे कि प्रधानमंत्री रैली कर सके अन्यथा चुनाव आचार संहिता लागू होते ही रैली नहीं हो सकती थी। लोकसभा का चुनाव कई महत्वपूर्ण राज्यों सें जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि में सात चरण में करवाया गया, जिससे प्रधानमंत्री मोदी, शाह व भाजपा को अपना चुनाव प्रचार करने का पर्याप्त अवसर मिल जाए और अन्य राज्यों से अपने कार्यकर्ताओं को वहां इकट्ठा किया जा सके। यह बड़ा शर्मनाक है कि मोदी जी व शाह दोनों चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का कोई अवसर नहीं गंवाते और चुनाव आयोग के निर्देशों का भी पालन नहीं करते।

देश की सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक बार पिंजरे का तोता कहा था। उसी प्रकार से चुनाव आयोग भी मोदी जी के हाथों में पिंजरे का तोता बन गया है।

प्रधानमंत्री व शाह के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन के मामले चुनाव आयोग के सामने आए तो चुनाव आयोग के हाथ कांपने लगे और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा। अगर मोदी जी व शाह जैसे भाषण कोई और विपक्ष का नेता देता है तो चुनाव आयोग उसे फ़ौरन नोटिस थमा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग के इस ढुल-मुल रवैये पर फटकार लगाई है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ़ आचार संहिता के उल्लंघन की अनेक शिकायते थी जिनमें से 5 शिकायतों पर गौर करने के लिये चुनाव आयोग की बैठक हुई और मोदीजी को तथाकथित क्लीन चिट दे दी गई, परंतु मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने अपनी विज्ञप्ति में चुनाव आयुक्त अशोक लवासा द्वारा किये गये प्रतिरोध का कोई जिक्र नहीं किया। इस प्रकार मोदी जी के खिलाफ़ दर्ज 5 शिकायतों में से एक भी शिकायत पर पूर्ण बहुमत से क्लीन चिट नहीं मिली है।

फ़रीदाबाद लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गूजर का जब गांवों में विरोध होने लगा तो उन्होंने अपनी रणनीति बदलकर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगने शुरू कर दिये। कृष्णपाल ने अपने हल्के के विकास के लिये कोई ठोस काम तो किये नहीं थे, इसलिये मतदाता उनके प्रति उदासीन हो गये। परंतु कृष्णपाल को आशा है कि लोग मोदी के नाम पर उन्हें वोट दे देंगे।, जिसका 'आम वोटर को विकास नहीं हताशा से भरा लग रहा है चुनाव-फ़रीदाबाद में कृष्णपाल की किश्ती मझधार में फ़ंसी लगती है' में उजागर किया गया है।

इस चुनाव में मोदी जी व शाह के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है लेकिन ईवीएम को लेकर लोगों में आशंका है कि भाजपा ईवीएम में गड़बड़ करके चुनाव जीत जाएगी। कुछ मतदाताओं का तो यह भी कहना था कि हम लम्बी-लम्बी लाइनों में क्यों खड़े हैं जबकि भाजपा ईवीएम के दम पर जीत ही जायेगी, जिसकी 'जीतेंगे... बेशक ईवीएम के दम पर सही...' में समीक्षा की गई है। भाजपा के मुकाबले विपक्ष का बूथ मैनेजमैंट भी लच्चर रहा है और अनेक बूथ पर भाजपा के अलावा अन्यकिसी राजनीतिक दल के पोलिंग एजेंट भी नहीं थे, जिससे भाजपा के पोलिंग एजेंट को पोलिंग पार्टी से मिलीभगत से भाजपा के पक्ष में फ़र्जी मतदान करने का मौका मिल गया।

इसका ज्वलंत उदाहरण है फ़रीदाबाद क्षेत्र का असावटी जहां के मतदान बूथ पर मतदान के दौरान गड़बड़ी का एक वीडियो बकायदा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें भाजपा का पोलिंग एजेंट बार-बार ईवीएम मशीन के पास जाकर असंवैधानिक तरीके से वोटिंग कर रहा है।

हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। सिर्फ़ हिसार को छोड़कर शेष सभी 9 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, जिसका 'हरियाणा की 10 संसदीय सीटों का चुनावी विश्लेषण-हरियाणा में मुकाबला 5-5,5-4या फ़िर 8-2...मज़दूर मोर्चा का आकलन !- जाट और पंजाबियों का वोट बुरी तरह से बंटने का फ़ायदा भाजपा उठाना चाहेगी' में सटीक विश्लेषण किया गया है। चुनाव परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि भाजपा जाट और पंजाबियों को बांटने में कितनी सफ़ल होती है और संभावना है कि कांग्रेस को कम से कम पांच सीट मिल जाएगी।

'सीएम सीटी में रिश्वतखोरी का खेल, खेल रहा है आइटीओ कालिया' तथा 'हूडा में भ्रष्टाचार खुलेआम अतिक्रमण व नियमों का उल्लंघन' में करनाल के आयकर विभाग तथा हूडा में व्याप्त भ्रष्टाचार का भंडा-फ़ोड़ किया गया है। यही हाल राज्य के अन्य विभागों का भी है जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावे पर करारा तमाचा है।

वर्तमान लोकसभा चुनाव में भाजपा का भविष्य प्रधानमंत्री मोदी पर टिका हुआ है और भाजपा को पूरा भरोसा है कि मोदी जी भाजपा को फ़िर से केन्द्र में सत्तारूढ करेंगे जबकि अन्धराष्ट्रवाद और पाकिस्तान का हौवा खड़ा करके पाकिस्तान के नाम पर चुनाव जीतने का मोदी जी को पूरा भरोसा है, जिसकी 'भाजपा का भरोसा मोदी में और मोदी का पाकिस्तान में... में आम लोगों के इंटरव्यू के आधार पर वास्तविक स्थिति का आकलन किया गया है।

श्री लंका में चर्च में ईसाइयों की ब्लॉस्ट में मृत्यु होने पर वहां के प्रधानमंत्री द्वारा क्षमा याचना करने जबकि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुलवामा के शहीदों पर राजनीति करने पर 'श्री लंका-हम क्षमा चाहते हैं, हम उनकी रक्षा करने में विफ़ल रहे;भारत-क्या आप अपना वोट पुलवामा शहीदों को समर्पित कर सकते हैं', प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नेहरू जी के बाद राजीव गांधी की आलोचना करने पर 'प्रधानमंत्री हमेशा युवाओं का ध्यान रखते हैं, देख, तभी तो राजनीति को नेहरू से राजीव की ओर मोड़ दिया है....', चुनाव आयोग द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट देने पर 'ईवीएम की तरह हमने क्लीन चिट मशीन भी बना ली, इधर बटन दवाओ उधर क्लीन चिट बाहर....' तथा सर! इतना ठीक है या और क्लीन करें' मोदी जी द्वारा नेहरू की कमिया निकालने पर मोदी की चलती है:नेहरू की गलती है', बेरोजगारों द्वारा नौकरी मांगने पर 'हमें नौकरी चाहिए!-लो इसे पहन लो:इसे पहनने से बेरोजगारी का एहसास नहीं होगा! (मैं भी चौकीदार)' तथा मोदी भक्तों द्वारा मोदी भक्ति का बढ़-चढ़ कर दिखावा करने पर 'भक्ति काल (1375-1700)मेरे तो गिरधर गोपाल -अन्ध भक्ति काल (2014-2019) हर-हर मोदी-घर-घर मोदी' कार्टूनों द्वारा मोदी जी की नीतियों पर उपयुक्त तंज कसा गया है।

पीपुल्स ट्रिब्युनल की रिपोर्ट में जूरी ने निष्कर्ष निकाला कि हिन्दुत्ववादी ताकतों द्वारा भारत में उच्च शिक्षा के विचार पर संस्थागत-सुनियोजित हमला किया जा रहा है तथा शैक्षणिक संस्थाओं के वातावरण को साम्प्रदायिक बनाया जा रहा है, जो विशेषकर पिछले चार वर्षों में गंभीर हो गया है, जिसका 'पीपुल्स ट्रिब्युनल की रिपोर्ट में दावा: पिछले 4 वर्षों से शिक्षा को किया जा रहा है साम्प्रदायिक और कैंपस हो रहे हैं आपराधिक' में सटीक विवेचन किया गया है। शिक्षित नागरिक ही सत्ता से सवाल पूछ सकते हैं, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिये आवश्यक है। इस लिये इस संकट की तरफ़ तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे उच्च शिक्षा के साथ-साथ भारतीय लोकतंत्र को सुरक्षित किया जा सके।